EDITORS CLUB OF INDIA

National Mission Manifesto

A Charter of Commitment to the Future
of Indian Editorial Leadership

1. संपादकीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय संरक्षण (National Editorial Independence Shield)

एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया यह घोषणा करता है कि भारत के हर संपादक को पूर्ण स्वतंत्रता मिलना उनका संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अनिवार्यता है। यह मैनिफ़ेस्टो पत्रकारिता को किसी भी संस्थागत, राजनीतिक, कॉर्पोरेट या बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करनेके लिए एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के संकल्प को दोहराता है। संगठन संपादकीय निर्णयों में किसी भी प्रकार के दबाव, सेंसरशिप, ब्लैकमेलिंग, या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दमन को राष्ट्र के चौथे स्तंभ पर हमला मानते हुए उसका प्रतिरोध करेगा। एक ऐसे भारत का निर्माण इस मिशन का लक्ष्य है जहाँ संपादकीय स्वतंत्रता केवल आदर्श न हो, बल्कि एक लागू किया गया राष्ट्रीय मानक हो।

2. फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार के विरुद्ध राष्ट्रीय लड़ाई (National War on Disinformation)

आज की डिजिटल दुनिया में गलत सूचना लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए ECI एक National Anti-Disinformation Command Centre स्थापित करने का संकल्प लेता है—जहाँ AI-सक्षम fact checking systems, सत्यापन प्रोटोकॉल, और देशभर के संपादकों के लिए रियल-टाइम सपोर्ट उपलब्ध होगा। यह केंद्र सोशल मीडिया, डिजिटल पोर्टल्स, प्रिंट और टीवी मीडिया में सक्रिय दुष्प्रचार नेटवर्क का विश्लेषण करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा और भारत के नागरिकों को एक तथ्य-संपन्न मीडिया वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेगा।

3.संपादक सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण मिशन (Editors Protection and Legal Security Act Movement)

भारत के कई हिस्सों में संपादको पर हमले, धमकियाँ, FIR का दुरुपयोग और संस्थागत प्रताड़ना सामान्य हो चुके हैं। एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया इस स्थिति को अस्वीकार्य मानते हुए संपादकों क़ी सुरक्षा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पर बल देता है। संगठन Editors Protection Act की आधिकारिक माँग रखता है, जिसमें—

- संपादको पर हमला संघेय अपराध घोषित हो एवं हमलों के मामलों में फास्ट-ट्रैक जांच
- FIR के दुरुपयोग पर प्रतिबंध
- विशेष अभियोजक की नियुक्ति
- एंटी-इंटिमिडेशन प्रावधान
- और संपादकों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों पर रोक

जैसे प्रावधान शामिल होंगे। यह मिशन मीडिया स्वतंत्रता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का ऐतिहासिक प्रयास बनेगा।

4. मीडिया नीति सुधार (Media Policy Reforms)

पारदर्शी और जवाबदेह मीडिया शासन की दिशा में एक राष्ट्रीय रूपरेखा भारत के मीडिया इकोसिस्टम में नीति अस्पष्टता और विनियामक असंतुलन लम्बे समय से चुनौती बने हुए हैं। इसलिए ECI एक व्यापक Media Policy Reform Framework विकसित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें—

- प्रेस स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय मानक
- डिजिटल मीडिया के लिए — नीति
- रेगुलेटर और मीडिया के बीच संतुलित संवाद
- सरकारी विज्ञापनों में पारदर्शिता
- और मीडिया हाउसों में जवाबदेही की संरचना

जैसे बिंदु शामिल होंगे। यह दस्तावेज़ भारत के भविष्य के मीडिया शासन की दिशा तय करेगा।

5. राष्ट्रीय संपादक नेतृत्व एवं क्षमता निर्माण अकादमी (National Editors Leadership & Capacity Building Academy)

प्रगतिशील राष्ट्र के लिए प्रगतिशील संपादकीय नेतृत्व अनिवार्य है। इसीलिए ECI एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने का संकल्प लेता है जो—

- संपादकीय नेतृत्व
- मीडिया नैतिकता
- डिजिटल पत्रकारिता
- Fact-checking तकनीक
- AI टूल्स
- Crisis reporting
- News room management

जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह अकादमी देश में भविष्य के संपादकीय नेतृत्व की नींव डालेगी।

6. डिजिटल पत्रकारिता के आधुनिकीकरण का राष्ट्रीय कार्यक्रम (Digital Newsroom Modernization Mission)

ECI डिजिटल मीडिया की शक्ति को समझते हुए एक व्यापक आधुनिकीकरण अभियान चलाएगा। इस कार्यक्रम के तहत—

- AI-सक्षम newsroom tools
- डेटा जर्नलिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर
- सत्यापन तकनीक
- आपदा एवं संघर्ष रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल
- साइबर सुरक्षा तंत्र

प्रत्येक सदस्य मीडिया संस्थान तक पहुँचाए जाएँगे। यह मिशन भारत को 21वीं सदी की संपादकीय प्रतिस्पर्धा में अग्रणी राष्ट्र बनाएगा।

7. सरकार–मीडिया संवाद का राष्ट्रीय संस्थागत ढाँचा (Government–Media Institutional Dialogue Forum)

एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार और मीडिया के बीच पारदर्शी संवाद आवश्यक है। ECI ऐसा स्थायी मंच बनाएगा जहाँ—

- नीति–निर्माण
- प्रेस स्वतंत्रता
- मीडिया की चुनौतियाँ
- और नागरिक अधिकारों

पर नियमित संस्थागत चर्चा होगी। यह मंच आपसी टकराव को कम करेगा और मीडिया व शासन के बीच संतुलन स्थापित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।

8. क्षेत्रीय और ग्रामीण संपादकों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान (Campaign for Empowerment of Regional and Rular Editors)

भारत की असली आवाज़ छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों के संपादकों के पास है, परंतु उन्हें संसाधनों और प्लेटफॉर्म की कमी का सामना करना पड़ता है। ECI इस अंतर को समाप्त करने के लिए—

- प्रशिक्षण
- टेक्नोलॉजी सहायता
- राष्ट्रीय नेटवर्किंग
- और संसाधनों तक पहुँच

उपलब्ध कराने का मिशन चलाएगा। यह अभियान ग्रामीण मीडिया को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने वाली सबसे बड़ी पहल बनेगा।

9. संपादक कानूनी सहायता प्रकोष्ठ (Editors Legal Support Cell)

किसी भी संकट—कानूनी, प्रशासनिक, या पेशेवर—में संपादकों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। ECI एक 24x7 Legal Support Cell का गठन करेगा जो—

- कानूनी परामर्श
- दस्तावेज़ी तैयारी
- आपातकालीन सहायता
- और राष्ट्रीय स्तर पर वकीलों का नेटवर्क

उपलब्ध कराएगा। यह सेल पत्रकारों की सुरक्षा को व्यावहारिक आधार प्रदान करेगा।

10.राष्ट्रीय मीडिया नैतिकता और जवाबदेही चार्टर (National Media Ethics & Accountability Charter)

एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया यह स्वीकार करता है कि पत्रकारिता के वल अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। इस दृष्टि से ECI एक उच्च-स्तरीय Ethics Charter जारी करेगा जिसमें—

- सत्य
- निष्पक्षता
- संवेदनशीलता
- जवाबदेही
- और नागरिक हित

को सर्वोच्च संपादकीय मूल्य घोषित किया जाएगा। यह चार्टर भारतीय मीडिया की नैतिक दिशा तय करेगा।

11. National Commitment to Editorial Leadership for Democracy, Civil Rights and Social Justice (लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए संपादकीय नेतृत्व का राष्ट्रीय संकल्प)

संपादक के वल समाचार प्रबंधक नहीं; वे लोकतांत्रिक चेतना के संरक्षक हैं। ECI यह अंतिम और सर्वोच्च संकल्प व्यक्त करता है कि भारत के हर नागरिक, हर आवाज़, हर मुद्दे और हर क्षेत्र को समान महत्व देते हुए संपादक अपनी भूमिका निभाएँगे। यह मिशन—

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- नागरिक अधिकार
- सामाजिक न्याय
- और निष्पक्ष दृष्टिकोण

को मीडिया का मूल स्तंभ बनाने का संकल्प है।